RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 341
दि. 14.04.2026, मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

लखनऊ प्लांट से ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी शुरू, बढ़ेगी सेना की ताकत

(जीएनएस)।

लखनऊ के नए ब्रह्मोस प्लांट से पहली मिसाइलें डिलीवर कर दी गई हैं. उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में बना यह प्लांट सालाना 80-100 ब्रह्मोस मिसाइलें बना सकता है. अक्टूबर 2025 में शुरू हुए प्लांट से चार मिसाइलों का पहला बैच तैयार किया गया है. इससे भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन मजबूत होगा. तीनों सेनाओं को मिसाइलें मिलना आसान हो जाएगा.

लखनऊ के नए प्लांट से पहली ब्रह्मोस मिसाइलें डिलीवर कर दी हैं. यह प्लांट उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है. अक्टूबर 2025 में यहां से ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला बैच तैयार किया गया, जिसमें चार मिसाइलें शामिल थीं. अब इन मिसाइलों की डिलीवरी शुरू हो गई है.

यह प्लांट भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बना सकता है. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के ठिकानों को बेहद तेज गति से नष्ट कर सकती है. इसका निर्माण अब भारत में ही हो रहा है, जो देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

लखनऊ प्लांट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है. इस कॉरिडोर को देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए शुरू किया गया था. प्लांट के शुरू होने से पहले ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण मुख्य रूप से हैदराबाद और अन्य जगहों पर होता था. अब लखनऊ में नया प्लांट शुरू होने से उत्पादन क्षमता बढ़ गई है. सप्लाई चेन भी मजबूत हुई है.

रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल

वित्तीय वर्ष 2025 (ऋ25) में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 1.50 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ब्रह्मोस प्लांट का शुरू होना इसी रिकॉर्ड का हिस्सा है. सरकार का लक्ष्य है कि रक्षा उत्पादन में विदेशी निर्भरता कम हो और ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में ही बने. ब्रह्मोस मिसाइल में अब 70 प्रतिशत तक लोकल कंटेंट का इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले काफी कम था.

राष्ट्रपति ने बैसाखी, विशु, विषुव, बोहाग बिहू, पोइला बैसाख, मेषादी, वैशाखादि और पुथांडु की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 14 और 15 अप्रैल, 2026 को मनाए जाने वाले बैसाखी, विशु, विषुव, बोहाग बिहू, पोइला बैसाख, मेषादी, वैशाखादि और पुथांडु की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा है:

"बैसाखी, विशु, विषुव, बोहाग बिहू, पोइला बैसाख, मेषादी, वैशाखादि और पुथांडु के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

ये त्यौहार फसल कटाई के मौसम के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न रूपों में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से, हम धरती माता और अन्नदाता किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कृषि परंपराएं और एकता भी इन त्योहारों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है।

"मैं कामना करती हूं कि ये त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं और हमें अपने राष्ट्र तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करें।"

प्रधानमंत्री ने हंगरी के संसदीय चुनाव में शानदार जीत के लिए श्री पीटर मैग्यार को बधाई दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री पीटर मैग्यार और टिस्जा पार्टी को उनकी शानदार चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत और हंगरी गहरे संबंधों, साझा मूल्यों और स्थायी आपसी सम्मान के बंधन से जुड़े हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने तथा दोनों क्षेत्रों के लोगों की साझा

समृद्धि और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु श्री मैग्यार के साथ मिलकर काम करने के प्रति आशान्वित हैं।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा:

"हंगरी के संसदीय चुनाव में शानदार जीत के लिए श्री पीटर मैग्यार और टिस्जा पार्टी को हार्दिक बधाई। भारत और हंगरी गहरी मित्रता, साझा मूल्यों और स्थायी आपसी सम्मान के बंधन से जुड़े हुए हैं। मैं हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा अपने लोगों की साझा समृद्धि और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु आपके साथ मिलकर काम करने के प्रति आशान्वित हूँ।

मुजफ्फरनगर में आयोजित रोजगार के 'महाकुंभ' में केन्द्रीय मंत्री श्री जयन्त चौधरी की उपस्थिति: 100+ कंपनियों से मिले युवाओं को सुनहरे अवसर

एनएसडीसी-नीति आयोग हएढ के साथ साझेदारी: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और रल्त्रॠ से जुड़ी महिलाओं को स्केलेबल उद्यमों की ओर ले जाने की पहल

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित नुमाइश ग्राउंड में आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) द्वारा एक भव्य एवं वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री जयन्त चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस मेले ने 'रोजगार के महाकुंभ' का रूप लिया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल भी शामिल हुए, जिन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए इस पहल को राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास, इनोवेशन और समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी की गईं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और नीति आयोग के Women Entrepreneurship Platform (WEP) के बीच एक Statement of Inftent (SOI) का आदान प्रदान किया गया। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाना और उन्हें पारंपरिक, सीमित आय वाले कार्यों से निकालकर औपचारिक, स्थाई और स्केलेबल उद्यमों में परिवर्तित करना है। इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों (रल्त्रॠ) से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता आधारित कौशल प्रशिक्षण, औपचारिक वित्तीय सहायता (क्रेडिट लिंकिंग), साझा एवं मानक-अनुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर, और घरेलू व वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, यह कार्यक्रम विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उनके प्रभाव को भी बढ़ाएगा। इस पहल से न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी को नई दिशा मिलेगी।

इसी कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और गूगल क्लाउड के सहयोग से तैयार एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया, जिसका शीर्षक है ह्लअक रील्लड्डेल्ल३ ल्लर्ि फ्री्रल्लीर२ह्व जो देश के युवाओं और शिक्षकों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति बढ़ती जागरूकता, स्वीकार्यता और आकांक्षाओं को दशार्ती है। रिपोर्ट के अनुसार 85 प्रतिशत से अधिक छात्र और 73 प्रतिशत शिक्षक एआई को भविष्य के लिए एक सकारात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति मानते हैं। 76 प्रतिशत युवा स्वयं एआई आधारित समाधान विकसित करने की इच्छा रखते हैं, जो भारत को 'कंज्यूमर' से 'क्रिएटर' बनने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है। 81 प्रतिशत शिक्षक शिक्षा में एआई के उपयोग को अपनाने के लिए तैयार हैं, जबकि 90 प्रतिशत छात्र अक को अपनी मातृभाषा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिससे तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। यह पहल शिक्षा क्षेत्र में 'पर्सनलाइज्ड एआई ट्यूटर' जैसी उन्नत अवधारणाओं को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में श्री रजत अरोड़ा, कंट्री मैनेजर - गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी, गूगल; डॉ. प्रदीप चौधरी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ; तथा प्रो. मर्दुल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ प्रोफेसर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ शामिल थे।

नोएडा प्रोटेस्ट से यूपी की सियासत गरमाई! 'ससम्मान इस गद्दी से उतर जाइए', अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा कटाक्ष

(जीएनएस)।

फैक्ट्री मजदूरों का सैलरी बढ़ोतरी वाला प्रदर्शन अब यूपी की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधते हुए तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने सीएम को 'ससम्मान गद्दी से उतर जाने' की सलाह दी और नक्सलवाद की साजिश वाले बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि '10 साल में आपने मजदूरों के लिए क्या किया कि हालात इतने बिगड़ गए?'

अखिलेश यादव का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह बयान न सिर्फ नोएडा प्रदर्शन को लेकर है, बल्कि महंगाई, भाजपा की नीतियों और प्रशासनिक नाकामी पर भी हमला है।

अखिलेश यादव का पूरा हमला- क्या कहा सपा प्रमुख ने?

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं तो एक सवाल जनता आपसे पूछ रही है कि अगर ये सच है तो आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल प्रचार करने गई थी या वनस्पति की खोजबीन में लीन थी या उसके प्रभाव में?'

उन्होंने आगे ये भी कहा कि 'मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले आप ये बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है कि 10 सालों में ऐसे हालात बन गए। आप मजदूरों के जख्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो न लगाएं, लेकिन उन जख्मों पर नमक तो न छिड़कें।'

अखिलेश ने महंगाई को भी भाजपा की कमीशनखोरी से जोड़ते हुए कहा कि 'भाजपाई कमीशनखोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवारवाले वैसे ही दुखी हैं। उसके ऊपर अवांछित दोषारोपण करने का जो पाप आप कर रहे हैं, वो घोर निंदनीय है। इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं।'

सबसे तीखा कटाक्ष ये रहा कि 'अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतरकर जाइए, नहीं तो जनता उतार देगी। भाजपाई खुद तो अंतिम दौर के भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, इसीलिए न इनसे देश संभल रहा है, न प्रदेश। भाजपा का डबल इंजन जनता के लिए ट्रबल इंजन बन गया है। जनता इन सब इंजनों के पहिए खोल देगी और पुर्जे निकालकर हमेशा के लिए कबाड़खाने में भेज देगी।'

सीएम योगी का पक्षः नक्सलवाद पुनर्जीवित करने की साजिश?

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ (उट ङ्क अ्रि३ि८ल्लइ३) ने रविवार (12 अप्रैल 2026) को स्पष्ट रूप से कहा था कि देश में नक्सलवाद लगभग समाप्त होने की स्थिति में है, लेकिन इसे पुनर्जीवित करने की साजिश हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुई दुखद घटना में जनहानि पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुई दुखद घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि वह इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखाः

'गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।'

लखनऊ में पड़ेगी भीषण गर्मी:40 डिग्री पार करेगा पारा, तेज पछुआ हवा से अभी राहत, कल से बदलेगा मौसम

लखनऊ में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने का दौर जारी है। इसके साथ ही तापमान में भी लगातार बढ़त हो रही है। इससे गर्मी का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा।

शनिवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.2 डिग्री कम रहा। अधिकतम आर्द्रता 59 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 20 फीसदी रहा। 1 सप्ताह के अंदर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। पछुआ आज से बंद हो जाएगी। बढ़ेगी गर्मी, 40 डिग्री पार करेगा पारा -

लखनऊ में पिछले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन 6-8त्त्ड की बढ़ोत्तरी दर्ज की है। अब भी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। दिन में 30-40 किमी/घंटे की गति से चल रही तेज पछुआ हवाओं का दौर 12 अप्रैल के बाद कम होगा।

'भारत, रूस और चीन की भूमिका अहम', अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। मुंबई में ईरान के महावाणिज्यदूत सईद रजा मोसयेब मोतलाघ ने बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने में प्रमुख वैश्विक शक्तियों, विशेषकर भारत की रचनात्मक भूमिका की सराहना की है।

नई दिल्ली की कूटनीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए मोतलाघ ने कहा कि भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर सैन्य हस्तक्षेप की बजाय वैश्विक शांति की बहाली को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी युद्धोन्माद को रोकने में भारत, रूस और चीन की भूमिका अहम होगी।

मोतलाघ ने बताया, "भारत, चीन और रूस ने अपने हितों को जोखिम में डालकर भी संघर्ष में हस्तक्षेप न करके यह प्रदर्शित किया है कि वे शांति चाहते हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले को उचित नहीं माना और न ही उसका समर्थन किया, न ही उन्होंने ईरान को सैन्य सहायता देने की स्थिति में खुद को रखा। बल्कि, उन्होंने शांति को बढ़ावा देने और आर्थिक बाजारों को स्थिर करने का प्रयास किया।" महावाणिज्यदूत ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि इन शक्तियों ने जिम्मेदार वैश्विक हितधारकों के रूप में कार्य किया है, फिर भी वॉशिंगटन की ओर से पारस्परिक सहयोग की कमी के कारण तनाव कम करने का मार्ग अवरुद्ध है। उन्होंने कहा, "हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक वे अमेरिका को समझाने में सफल नहीं हुए हैं। फिर भी, इन तीनों प्रमुख शक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अमेरिका को युद्धोन्माद बंद करने के लिए राजी करने और इजरायल की निरंकुश और दमनकारी सरकार पर दबाव डालने के लिए अपना प्रभाव डालें।

24 साल बाद लखनऊ स्थित विधान भवन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पुरानी यादों को किया ताजा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 साल बाद लखनऊ के विधान भवन का दौरा किया। उन्होंने वहां हुए व्यापक नवाचारों, डिजिटल गैलरी और आधुनिक व्यवस्थाओं की सराहना ..

रविवार को विधान भवन के निरीक्षण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनकी तस्वीर भेंट करते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

राजनाथ सिंह ने 24 साल बाद विधान भवन का भ्रमण किया।

उन्होंने डिजिटल गैलरी और आधुनिक व्यवस्थाओं की सराहना की।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात कर सेल्फी ली।

लखनऊ। (जीएनएस)। विधान भवन में रविवार दोपहर को एक अलग परिदृश्य उभरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 साल बाद विधान भवन में भ्रमण करते नजर आए। उन्होंने विधान भवन के विभिन्न हिस्सों में किए गए बदलावों एवं प्रयोगों की सराहना की। विधान भवन में अपने बीते हुए पलों का स्मरण सबसे साझा किया।

दोपहर करीब 12 बजे राजनाथ सिंह विधान भवन पहुंचे, जहां सतीश महाना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने यहां किए गए व्यापक नवाचारों, सुदृढ़ व्यवस्थाओं तथा आधुनिकीकरण कार्यों की सराहना की।

सबसे पहले डिजिटल गैलरी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के गौरवमयी इतिहास पर आधारित एक विशेष फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि यहां किए गए ये नवाचार जनप्रतिनिधियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जिससे विधायी कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर ने कैडेटों के लिए राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया

(जीएनएस)। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से कैडेटों को साइबर जागरूकता, डिजिटल स्वच्छता और व्यावहारिक साइबर सुरक्षा कौशल में संरचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और एनआईईएलआईटी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी की उपस्थिति में एनसीसी और एनआईईएलआईटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

पहले चरण में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम होगा। यह एक 15 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल है। इसे डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर स्वच्छता और साइबर खतरों के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह चरण

देश भर के सभी पंजीकृत एनसीसी कैडेटों के लिए खुला रहेगा और इसे एनआईईएलआईटी डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

दूसरे चरण में साइबर रक्षा कार्यक्रम होगा। यह एक गहन 60 घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण है। इसे योग्यता-आधारित स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित कैडेटों के लिए तैयार किया गया है। इस चरण में व्यावहारिक प्रशिक्षण, वास्तविक जीवन के सिमुलेशन और साइबर सुरक्षा उपकरणों और तकनीकों के व्यावहारिक अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे कैडेट साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से पहचानने और उनसे निपटने में सक्षम होंगे।

इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर साइबर जागरूकता फैलाना, सुरक्षित डिजिटल तौर-तरीकों को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा पहलों का समर्थन करने में योगदान देने के लिए प्रशिक्षित एनसीसी साइबर कैडेटों का एक समूह तैयार करना है। यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भी है।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े केस में दिल्ली हाई कोर्ट कर रहा सुनवाई, अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे अपनी पैरवी

(जीएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह याचिका दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती है।

इस मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब केजरीवाल ने स्वयं न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा से मामले की सुनवाई से हटने, जिसे न्यायिक शब्दावली में 'रिक्यूजल' कहते हैं, का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया। वह व्यक्तिगत तौर पर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल आज हाई कोर्ट जाएंगे। उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई दोपहर में होगी। अरविंद केजरीवाल खुद अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अपनी पुनर्विचार याचिका दायर की है।

रिक्यूजल आवेदन पर पहली सुनवाई 6 अप्रैल को हुई थी, जहाँ न्यायालय ने सीबीआई से केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था। 6 अप्रैल की सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इस रिक्यूजल याचिका का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया कि केजरीवाल का आवेदन "आधारहीन आरोपों" पर आधारित है। सीबीआई ने भी रिक्यूजल आवेदन का विरोध करते हुए अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया दाखिल कर दी है।

न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि निचली अदालत ने जिस तरह सीबीआई के गवाहों को सरकारी गवाह बनाया, "उनका आचरण एक सुनियोजित परिणाम साबित करने वाला था।" उन्होंने आगे कहा, "अंततः निचली अदालत ने मुझे पूरी तरह से आरोपमुक्त कर दिया, जिसके निष्कर्ष इस अदालत के निष्कर्षों के बिल्कुल विपरीत थे, इसलिए मेरे मन में एक शंका है।"

इस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने पलटवार करते हुए पूछा, "आपकी दलीलें क्या हैं? क्योंकि आपने कहा है कि निचली अदालत के उस फैसले को गलत बताया गया है... जिस वक्त मैंने फैसला किया उस समय इस अदालत (ट्रायल कोर्ट) का तो फैसला हुआ नहीं था। निचली अदालत के आदेश पर हम तब जाएंगे जब वे इस पर निर्णय लेंगे। आज हम सिर्फ रिक्यूजल के मुद्दे पर आपकी बात सुन रहे हैं।"

केजरीवाल ने आगे दलील दी कि सरकारी गवाहों से जुड़ा एक मुद्दा उठा था, जिस पर अदालत की अपनी एक 'फाइंडिंग' है। उन्होंने कहा कि "इस पर भी एक अंतिम फाइंडिंग दे दी गई थी। मुझे लगभग भ्रष्ट घोषित कर दिया गया था। मुझे लगभग दोषी घोषित कर दिया गया था। बस सजा सुनानी रह गई थी।" पीठ ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा, "मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह आपकी सोच है।"

केजरीवाल ने बताया कि इस न्यायालय के सामने पहले भी पांच मामले आ चुके हैं। उनके स्वयं की गिरफ्तारी का मामला, संजय सिंह, के. कविता और अमन ढाल के जमानत आवेदन शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इन मामलों में अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ "फैसले के समान" थीं, जो एक तरह से अंतिम निर्णय का आभास देती थीं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 'सत्येंद्र जैन बनाम ईडी' मामले में इसी अदालत के फैसले का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उस मामले में जमानत की सुनवाई चल रही थी और छह दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जब ईडी ने अचानक न्यायाधीश पर 'भय या पूर्वाग्रह की आशंका' जताई। जिला न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय ने भी अनुमति दे दी थी।

केजरीवाल ने बताया कि उस मामले और उनके मामले में काफी समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि उस मामले में न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि "सवाल न्यायाधीश की ईमानदारी का नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता के मन में उत्पन्न आशंका का है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मामला भी ठीक वैसा ही है, जहाँ न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा पर नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता के मन की आशंका पर विचार किया जाना चाहिए।

केजरीवाल ने न्यायाधीशों के रिक्यूजल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 'रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ' फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साफ तौर पर कहा है कि "न्यायाधीश को यह नहीं देखना है कि वह पक्षपाती नहीं हैं, बल्कि अगर पार्टी के मन में पक्षपात की शंका है, तो रिक्यूजल का मामला बनता है।" इसी कारणवश, केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराई।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "मेरे मन में जो आशंका है वह मेरे और अदालत के बीच का मामला है। सीबीआई को इस मामले में पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए।" केजरीवाल ने अपनी बात दोहराई कि उनके मन में न्याय को लेकर आशंका है, और यह मामला केवल अदालत और उनके बीच का है।

केजरीवाल ने बताया कि 9 मार्च का आदेश आने पर "मेरा दिल बैठ गया।" उन्हें पूर्वाग्रह की गंभीर आशंकाएं थीं, जिसके चलते उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। मुख्य न्यायाधीश ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने यह आवेदन न्यायालय में दाखिल किया।

उन्होंने 9 मार्च के आदेश पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, "9 मार्च को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सीबीआई के अलावा कोई मौजूद नहीं था। एकतरफा (एक्स-पार्टे), बिना किसी की सुनवाई किए, बिना किसी का जवाब लिए इस अदालत ने आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया आदेश गलत है।" केजरीवाल ने हैरानी व्यक्त की कि जिस आदेश को निचली अदालत ने पूरे दिन की सुनवाई और 40,000 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद पारित किया था, उसे उच्च न्यायालय ने मात्र पांच मिनट की सुनवाई के बाद "त्रुटिपूर्ण" घोषित कर दिया।

लखनऊ के मलिहाबाद में विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक में मारी टक्कर, महिला की मौत; तीन घायल

पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया, मृतका के शव को कब्जे में लिया

मलिहाबाद थाना क्षेत्र का हादसा, कार चालक के खिलाफ की जा रही कार्रवाई

मलिहाबाद। (जीएनएस)। सड़क पर लापरवाही और तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। मलिहाबाद में विपरीत दिशा से आ रही कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक मासूम समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और स्थिति को सामान्य किया।

मनकौटी निवासी तालिब अपनी भाभी 35 वर्षीय जुल्फी और पांच वर्षीय भतीजे जुहैब को मायके छोड़ने के लिए उन्नाव के नियाज अली खेड़ा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वह विपरीत दिशा से सफर कर रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक भतोइया गांव स्थित आरआर लान के पास पहुंची, सामने से तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क किनारे खाई में जा गिरे। वहीं कार भी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। हादसे में तालिब, जुल्फी और जुहैब गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार सवार संडीला के काजीपुर निवासी रोहित को भी गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु में वर्षा का दीर्घकालिक पूर्वानुमान

देश में 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसमी (जून से सितंबर) वर्षा के सामान्य से कम रहने की संभावना है (दीर्घकालीन औसत (एलपीए) का 95-90%)

देश में मौसमी वर्षा एलपीए का 92% रहने की संभावना है। इसमें मॉडल त्रुटि ± 5% है। 1971-2020 की अवधि के आधार पर देश में मौसमी वर्षा का एलपीए 87 सेंटीमीटर है

भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में कमजोर ला नीना जैसी स्थितियां ई एन एस ओ-तटस्थ स्थितियों में परिवर्तित हो रही हैं

उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय परिसंचरण विशेषताएं कमजोर ला नीना जैसी स्थितियों के अनुरूप बनी हुई हैं

मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (एमएमसीएफएस) दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो स्थितियों के तैयार होने का सुझाव देती है

हिंद महासागर में तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) स्थितियां मौजूद हैं और नवीनतम जलवायु मॉडल पूर्वानुमान इंगित करता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के अंत तक सकारात्मक आईओडी स्थितियां विकसित होने की संभावना है

उत्तरी गोलार्ध में अंतिम तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2026) के दौरान हिम आवरण का विस्तार उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में सर्दियों और वसंत ऋतु में बर्फ की मात्रा सामान्य से थोड़ी कम रही। देश में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के साथ इसका सामान्यतः विपरीत संबंध है

मौसम विभाग मई 2026 के अंतिम सप्ताह में मानसून मौसम की वर्षा के अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा

(जीएनएस)। 2003 से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) देश भर में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून-सितंबर) वर्षा के औसत पूर्वानुमान को दो चरणों में जारी करता आ रहा है। पहले चरण का पूर्वानुमान अप्रैल में और दूसरे चरण का अद्यतन पूर्वानुमान मई के अंत तक जारी किया जाता है। 2021 में आईएमडी ने वर्तमान दो-चरणीय पूर्वानुमान रणनीति में संशोधन करते हुए, देश भर में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के मासिक और मौसमी पूर्वानुमान जारी करने के लिए एक नई रणनीति शुरू की। नई रणनीति में गतिशील और सांख्यिकीय दोनों पूर्वानुमान प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। गतिशील पूर्वानुमान प्रणाली में आईएमडी के मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (एमएमसीएफएस) सहित विभिन्न वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान केंद्रों के वैश्विक जलवायु मॉडल (सीजीसीएम) पर आधारित मल्टी-मॉडल एन्सेम्बल (एमएमई) पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

नई एलआरएफ रणनीति के अनुसार अप्रैल के मध्य में जारी किए गए पहले चरण के पूर्वानुमान में पूरे देश के लिए मात्रात्मक और पूर्वानुमान और देश भर में मौसमी (जून-सितंबर) वर्षा की तृतीय श्रेणियों (सामान्य से ऊपर, सामान्य और सामान्य से नीचे) के लिए पूर्वानुमानों का स्थानिक वितरण शामिल है।

मई के अंत में जारी किए गए दूसरे चरण के पूर्वानुमान में अप्रैल में जारी किए गए मौसमी वर्षा पूर्वानुमान के अद्यतन के साथ-साथ भारत के चार समरूप क्षेत्रों (उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्व भारत) और मानसून कोर जोन (एमसीजेड) में मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण के पूर्वानुमान के दौरान देश के लिए मात्रात्मक और पूर्वानुमान और जून की वर्षा की तृतीय श्रेणियों (सामान्य से अधिक, सामान्य और सामान्य से कम) के लिए पूर्वानुमानों का स्थानिक वितरण भी जारी किया जाता है।

उपरोक्त पूर्वानुमानों के क्रम में अगले एक महीने के लिए मासिक वर्षा पूर्वानुमान क्रमशः जून, जुलाई और अगस्त के अंत में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश के लिए मात्रात्मक और पूर्वानुमान और मौसम के दूसरे भाग के लिए तृतीय श्रेणियों के पूर्वानुमानों का स्थानिक वितरण जुलाई के अंत में अगस्त के पूर्वानुमान के साथ जारी किया जाता है।

1. देश भर में वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून-सितंबर) में होने वाली वर्षा का पूर्वानुमान।

गतिशील और सांख्यिकीय दोनों मॉडलों पर आधारित पूर्वानुमान से पता चलता है कि मात्रात्मक रूप से मानसून की मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 92% होने की संभावना है। इसमें मॉडल त्रुटि ± 5% है। 1971-2020 की अवधि के लिए देश भर में मौसमी वर्षा का एलपीए 87 सेंटीमीटर है।

देश भर में मौसमी (जून से सितंबर) वर्षा के लिए पांच श्रेणियों का पूर्वानुमान नीचे दिया गया है। पूर्वानुमान से पता चलता है कि सामान्य से कम और अपर्याप्त वर्षा दोनों श्रेणियों की संभावनाएँ उनके संबंधित जलवायु संबंधी संभावनाओं से अधिक हैं। सामान्य से अधिक और अत्यधिक वर्षा श्रेणियों की पूर्वानुमानित संभावनाएँ उनके संबंधित जलवायु संबंधी संभावनाओं से कम हैं। कुल मिलाकर, देश भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा सामान्य से कम (एलपीए का 90-95%) रहने की सबसे अधिक संभावना है।

2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसमी वर्षा के लिए एमएमई का पूर्वानुमान अप्रैल की प्रारंभिक स्थितियों के आधार पर और भारतीय मानसून क्षेत्र में उच्चतम पूर्वानुमान कौशल वाले जलवायु मॉडलों के एक समूह का उपयोग करके तैयार किया गया था।

जून से सितंबर तक की मौसमी वर्षा के लिए संभाव्यता पूर्वानुमानों की तृतीय श्रेणियों (सामान्य से अधिक, सामान्य और सामान्य से कम) का स्थानिक वितरण चित्र 1 में दर्शाया गया है। स्थानिक वितरण से पता चलता है कि पूर्वोत्तर, उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम मौसमी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। यहां सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। भूमि क्षेत्र के भीतर सफेद रंग से चिह्नित क्षेत्र मॉडल से कोई संकेत नहीं दर्शाते हैं।

2. भूमध्यरेखीय प्रशांत और हिंद महासागरों में समुद्र की सतह के तापमान (एसएसटी) की स्थितियाँ

वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में कमजोर ला नीना जैसी स्थितियाँ ई एन एस ओ-तटस्थ स्थितियों में परिवर्तित हो रही हैं। हालांकि उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में कुछ वायुमंडलीय परिसंचरण विशेषताएँ कमजोर ला नीना जैसी स्थितियों के अनुरूप बनी हुई हैं। मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली के नवीनतम पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि अप्रैल से जून 2026 के मौसम के दौरान ई एन एस ओ-तटस्थ स्थितियाँ जारी रहने की सबसे अधिक संभावना है। मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अल नीनो की स्थितियों के विकसित होने का संकेत देती है।

वर्तमान में हिंद महासागर पर तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) की स्थिति मौजूद है और नवीनतम जलवायु मॉडल पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के अंत तक सकारात्मक आईओडी की स्थिति विकसित होने की संभावना है।

प्रशांत और हिंद महासागरों में समुद्र की सतह के तापमान (एसएसटी) की स्थिति का भारतीय मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) इन महासागरीय बेसिनों में समुद्र की सतह की स्थितियों के विकास की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है।

3. उत्तरी गोलार्ध पर हिम आवरण

पिछले तीन महीनों (जनवरी से मार्च 2026) के दौरान उत्तरी गोलार्ध में हिमपात का विस्तार सामान्य से थोड़ा कम रहा। उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में शीतकालीन और वसंतकालीन हिमपात का विस्तार, देश में होने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के साथ सामान्यतः विपरीत संबंध रखता है। 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून-सितंबर) के दौरान भारत में मौसमी वर्षा की तृतीय श्रेणियों* (सामान्य से कम, सामान्य और सामान्य से अधिक) का पूर्वानुमान। यह चित्र सबसे संभावित श्रेणियों और उनकी संभावनाओं को दर्शाता है। सफेद छायांकित क्षेत्र मॉडल से कोई संकेत न मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। (*तृतीय श्रेणियों की जलवायु संबंधी संभावनाएं समान हैं प्रत्येक 33.33%)।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नवप्रवर्तकों को एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन 2026 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है

एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन का उद्देश्य मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत, मैन्युअल कार्य को कम करने, दावों के निपटान में तेजी लाने और मापनीय, भविष्य के लिए निर्णयों की रूपरेखा बनाने के लिए अभिनव डिजिटल समाधान तैयार करना है

पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है, अब तक कुल 2,600 से अधिक प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है; मास्टरक्लास श्रृंखला 13 अप्रैल से शुरू होगी

(जीएनएस)। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई), सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना देश में डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन को गति प्रदान कर रही है और प्रतिदिन लगभग 50,000 दावों का निपटान 1,900 से अधिक उपचार पैकेजों के तहत कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर

दावों के निपटान में गति, सटीकता और अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में 15-20 प्रतिशत दावों का निपटान स्वतः हो जाता है, फिर भी एक ऐसे समाधान की आवश्यकता बनी हुई है जो सभी पैकेजों के लिए उपयुक्त हो और सभी पर लागू हो सके।

दावों की संख्या और जटिलता को देखते हुए विभिन्न प्रकार के उपचारों और दस्तावेज स्वरूपों को संभालने में सक्षम एक उन्नत स्वचालित निर्णय प्रणाली की आवश्यकता बढ़ रही है। स्वचालन, एआई-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने, मानकीकृत दस्तावेजीकरण का तत्क्षण लाभ उठाकर दावों की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा सकता है, जिससे अधिक सुसंगत और पारदर्शी परिणाम शीघ्र प्राप्त हो सकें।

एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन का उद्देश्य ऐसे अभिनव डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना है जो मौजूदा एबी पीएम-जेएवाई बुनियादी ढांचे के साथ सहजता से एकीकृत हों, मैन्युअल प्रयासों को कम करें, निपटान समय को कम करें और पूरे इकोसिस्टम के लिए एक मापनीय, भविष्य के लिए निर्णय ढांचा तैयार करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-अजूडकेशन हैकाथॉन 2026 के लिए शानदार प्रतिक्रिया मिली है, अब तक देश भर से 2,600 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है।

पंजीकरण की अंतिम तिथि: 13 अप्रैल 2026

इच्छुक छात्र, शोधकर्ता, डेवलपर, पेशेवर, स्टार्टअप और नवप्रवर्तक 13 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

तीन मास्टरक्लास सत्र 13 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे

प्रतिभागियों को चुनौतियों को समझने और संभावित समाधानों की पहचान करने में सहायता करने के लिए एनएचए 13 अप्रैल 2026 से तीन मास्टरक्लास श्रृंखला का आयोजन करेगा। सत्रों में दावा निपटान प्रणाली, हैकाथॉन से प्रमुख अपेक्षाएं और डिजिटल स्वास्थ्य में नवाचार के उभरते अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जाएगी।

मास्टरक्लास श्रृंखला का कार्यक्रम इस प्रकार है:

सत्र 1: 13 अप्रैल 2026` दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

सत्र 2: 15 अप्रैल 2026` दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

सत्र 3: 16 अप्रैल 2026` दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

सभी सत्रों का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आधिकारिक यूट्यूब चैनल @अ८४र्ट्रैल्तठल्स पर भी किया जाएगा।

आईआईएससी बेंगलुरु में भव्य समापन समारोह

हैकथॉन का समापन 8-9 मई, 2026 को बेंगलुरु स्थित प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान में होगा, जहां विजेता टीमें स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र के दिग्गजों की निर्णायक समिति के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत करेंगी। विजेताओं को प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए 5 लाख 3 लाख और 2 लाख रुपये के आकर्षक नकद पुरस्कार के साथ-साथ एनएचए के साथ संभावित सहयोग का अवसर भी मिलेगा।

डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार को आगे बढ़ाना

यह हैकाथॉन एनएचए के भविष्य के लिए तैयार डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास के लिए नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। जो दक्षता तथा पारदर्शिता को मजबूत बनाकर लाभार्थियों और प्रदाताओं दोनों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण को बेहतर बनाता है।

प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री ने परोपकारी शक्तियों को पोषित करने पर एक संस्कृत सुभाषित साझा किया

नई दिल्ली, (जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान हमारे लोगों के अडिग साहस की एक सशक्त याद दिलाता है।

प्रधानमंत्री ने आज एक संस्कृत सुभाषितम् भी साझा किया, जिसमें समाज में परोपकारी शक्तियों के पोषण का आह्वान किया गया है, जो राष्ट्र को समृद्ध, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती हैं, साथ ही विभाजन, अन्याय और असंतोष उत्पन्न करने वाली विनाशकारी शक्तियों का दृढ़ता से प्रतिरोध करने का संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा: 'आज के दिन हम जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान हमारे लोगों के अडिग साहस की एक सशक्त याद दिलाता है। उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया साहस और दृढ़ संकल्प पीढ़ियों को स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहता है।' 'जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी अमर बलिदानियों को मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।'

इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्।
अपघ्नन्तो अराव्णः॥"

हे परिश्रमी लोगों! अपने समाज में उन परोपकारी शक्तियों का पोषण करें, जो राष्ट्र को समृद्ध, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती हैं। साथ ही, उन विनाशकारी शक्तियों का दृढ़ता से प्रतिरोध करें, जो समाज में विभाजन, अन्याय और असंतोष उत्पन्न करती हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

लगभग प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में वैमनुष्यता के जहर का इलाज करना होगा

कुचलना होगा देश में पनपते आतंकवादी समूह को, देश के आन्तरिक हालातों को उत्तरदाई तंत्र में बैठे जिम्मेदार लोग किन्हीं खास कारणों से निरंतर अदृष्टिगत करते चले जा रहे हैं। उधार लेकर घी पीने वाले तंत्र के आन्तरिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं मगर सत्ता हथियाने के लिए कभी लैपटाप बांटे जाते हैं तो कभी स्कूटी। वर्तमान परिस्थितियों से समूचा संसार जूझ रहा है। पाकिस्तान में हुई शान्ति वार्ता का विफल होना एक नये संकट का शंखनाद माना जा रहा है। ईरान संरक्षित हिजबुल्लाह, हूती, हमाज जैसी दहशतगर्द जमातें खुलेआम मिसाइल, ड्रोन और राकेट लांचर सहित अत्याधुनिक हथियारों से हमले कर रहे हैं। आतंक परस्त देशों के कवच में कट्टरपंथी जमातें दहशतगर्दो की फौजें तैयार करने में जुटे हैं। अमन, चैन, भाईचारे को गजवा-ए-दुनिया निगलती जा रही है। कहीं यहूदियों को समाप्त करने की धमकियां दी जा रहीं हैं तो कहीं हिन्दुओं को। ईसाई और पारसियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह हालात दुनिया के साथ-साथ देश के अन्दर भी बेलगाम होते जा रहे हैं। अतीत गवाह है कि ईंश निदा के मनगढन्त आरोप लगाकर सर तन से जुदा करने वाली प्रायोजित भीड एकत्रित की जाती है और फिर पूर्व नियोजित षडयंत्र को अमली जामा पहना दिया जाता है। राष्ट्रविरोधी ताकतें सीमापार से मिलने वाले धन से कट्टरता को पोषित कर रहीं हैं, भय का वातावरण र्निमित कर रहीं है और बना रहीं है आन्तरिक युद्ध के हालात। देश के लगभग प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में वैमनुष्यता का जहर पैल चुका है जिसे खास धरमिक स्थानों से निरंतर संरक्षण दिया जा रहा है। हर जगह अवसरवादियों की जमातें मौके की तलाश में हैं। किसी भी मनगढन्त मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से पैलाकर देश भर में अशान्ति पैलाने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं जिस पर उत्तरदायी तंत्र द्वारा हमेशा ही बेखबर होने का ढोंग रचा जाता रहा है। सरकारी जमीनों पर अतिव्रमण करके मकान, दुकान, कारखाने लगाये जा रहे हैं। इन अवैध निमार्णों को सोची समझी योजना के तहत सकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें के साथ तैयार किया जाता है ताकि सुरक्षाबलों की आमद के दौरान आामण की व्यूह रचना का लाभ उठाया जा सके। देश की लगभग हर बसाहट में खास झंडा लगाकर अपनी उपस्थिति, कट्टरता और एकता का सबूत देने वाले जुल्म की नईं इबारत लिखने में लगे हैं जिस पर कार्यपालिका जानबूझकर मौन धारण रखे हुए है। इन अवैध परिसरों में अवैध ढंग से विद्युत, जल और शासकीय सुविधाओं का खुलकर निःशुल्क उपयोग हो रहा है। ऐसे लगभग सभी स्थानों पर स्थानीय निकायों ने सुविधाओं का अम्बार भी लगा दिया है। जनप्रतिनिधियों ने वोट बैंक के लिए अनेक अवैध निमार्णों को वैध कराना भी शुरू कर दिया है। इन स्थानों को अभेद किले के रूप में परिर्वितित किया जा चुका है जो आने वाले समय में आामण का केन्द्र बनेंगे। इन स्थानों पर भारी मात्रा में अवैध असलहे, गोलाबा रूद और घातक संसाधन मौजूद होने की खबरें भी निरंतर आ रहीं हैं। धर्म के नाम पर उन्माद पैलाने वाली अनेक पाठशालाओं में जहरीली पौध तैयार की जा रही है। लगभग हर आबादी में ऐसे आतंकी संगठन मौजूद है जिन्हें खूनी खेल खेलने में महारत हासिल है। अनेक राजनैतिक दलों के कद्दावर नेताओं से लेकर लालफीताशाही की एक खास विरादरी खुलकर उनके साथ खडी दिखती है। नियम, कानून और कायदे केवल निरीह, गरीब और लाचार तक ही सीमित होकर रह गये हैं या फिर जुल्मी को बचाने हेतु संविधान की धारायें प्रयुत्त होतीं हैं। भीड तंत्र के आगे कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह नतमस्तक हो चुकी है। वोट बैंक बढाने की मानसिकता अब दावानल बनकर उभर चुकी है। आार्य है कि धरातल की वास्तविक स्थिति को नजरंदाज करते हुए चुनावी धरातल पर मुफ्तखोरी की निरंतर घोषणायें हो रहीं हैं। ऐसे राजनैतिक दलों को अपने घोषणा-पत्रों की परूति हेतु पाटा पंड से खर्च करना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि जनता पर टैक्स का दबाव बढाकर हरामखोरों की फौज तैयार करके उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों हेतु सुगम समय प्रदान करने वाले राजनैतिक दल ही सत्ता सुख की चाह में आत्मघाती कदम उठा रहे हैं।

दिल्ली में इलाज महंगा, लखनऊ में सस्ता, जानें कैसे आपकी लोकेशन तय करती है प्रीमियम

(जीएनएस)।

क्या आप जानते हैं कि लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होते ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 50% तक बढ़ सकता है? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां आपके रहने की जगह के हिसाब से पैसे वसूलती हैं. आसान भाषा में कहें तो शहर बदलने के साथ केवल आपका पता और माहौल ही नहीं बदलता, बल्कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बदल जाता है.

शहर शिफ्टिंग से पहले समझें इंश्योरेंस के ये गणित.

नई दिल्ली. अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, शहर बदलने का असर सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल या खर्चों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इससे सीधे प्रभावित होती है. क्या आप जानते हैं कि लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होते ही आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 50% तक बढ़ सकता है? सुनने में यह किसी छिपी हुई लागत जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बीमा कंपनियों का एक ठोस गणित काम करता है.

क्यों बदल जाते हैं प्रीमियम?

हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम तय करते समय आपके शहर को एक अहम फैक्टर मानती हैं. कंपनियां प्रीमियम तय करने के लिए 'जोन-बेस्ड प्राइसिंग' (ड्ढल्ली-इंरीढ्ढ्रल्ल्) का इस्तेमाल करती हैं. आसान भाषा में कहें तो, बीमा कंपनियां भारत के शहरों को उनके मेडिकल खर्चों के आधार पर अलग-अलग जोन में बांटती हैं.

जोन 1: इसमें दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे महानगर आते हैं, जहां इलाज सबसे महंगा है.

जोन 2: इसमें लखनऊ, जयपुर, पुणे और कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं.

जोन 3: इसमें छोटे शहर और ग्रामीण इलाके आते हैं.

बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तय करने के लिए किस आधार पर शहरों को जोन में बांटती हैं?

अशिक्षा स्तर के आधार पर

इमेडिकल खर्चों के आधार पर

उमौसम के आधार पर

ऊजनसंख्या के आधार पर कंपनियां

उदाहरण के लिए अगर एक 25 साल आदमी दिल्ली (जोन 1) में रहता है, तो उसे एक बेसिक कवर के लिए लगभग 15,111 रुपये चुकाने

पड़ सकते हैं. वहीं, वही आदमी अगर लखनऊ (जोन 2) में रहता है, तो उसका प्रीमियम गिरकर लगभग 10,012 रुपये हो जाएगा. यह अंतर इसलिए है क्योंकि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस और सर्जरी का खर्च लखनऊ की तुलना में कहीं ज्यादा होता है.

अस्पताल एक, बिल अलग-अलग

पॉलिसीबाजार के एक्सपर्ट के अनुसार, एक ही ब्रांड के अस्पताल का बिल अलग-अलग शहरों में अलग हो सकता है. उदाहरण के तौर पर, मेदांता जैसे अस्पताल में 'अपेंडिक्स' का ऑपरेशन अगर किसी छोटे शहर में 80,000 रुपये से 1.2 लाख रुपये के बीच होता है, तो वही प्रक्रिया दिल्ली के अस्पताल में 2 लाख रुपये के पार जा सकती है.

सस्ती पॉलिसी का 'छिपा हुआ खतरा'

अक्सर लोग प्रीमियम के पैसे बचाने के चक्कर में छोटे शहर (लोअर जोन) के पते पर पॉलिसी ले लेते हैं. लेकिन यह बचत क्लेम के समय भारी पड़ सकती है. अगर आपके पास जोन-3 की पॉलिसी है और आप अचानक दिल्ली जैसे जोन 1 के अस्पताल में इलाज कराते हैं, तो कंपनियां 'को-पेमेंट' क्लॉज लागू कर देती हैं. इसका मतलब यह है कि अस्पताल के कुल बिल का एक निश्चित हिस्सा (जैसे 20% या 30%) आपको अपनी जेब से भरना होगा.

सही चुनाव कैसे करें?

इंश्योरेंस एक्सपर्ट की सलाह है कि पॉलिसी लेते समय केवल 'आज' का पता न देखें, बल्कि यह सोचें कि इमरजेंसी में आप कहां इलाज कराना चाहेंगे. अगर आप अक्सर सफर करते हैं या भविष्य में मेट्रो शहर जाने की संभावना है, तो 'पैन-इंडिया' बेस्ड प्रीमियम चुनें. अगर आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, तो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दें. जानकारी छुपाने पर क्लेम खारिज भी हो सकता है.

राष्ट्रपति ने एम्स राजकोट के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित किया

"समाज में गहरा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं कुशल और सामाजिक रूप से जागरूक डॉक्टर ": राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स राजकोट के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर उसकी गरिमा बढ़ाई।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि किफायती लागत पर विश्व स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए देश भर में कई एम्स स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलकदमियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए अनुसंधानों और मरीजों की देखभाल के जरिये स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के प्रति एम्स की प्रतिबद्धता सराहनीय है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स राजकोट एक नया संस्थान है। चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और सेवा के क्षेत्रों में इसे अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। उन्होंने एम्स राजकोट के नीति निमार्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने उद्देश्यों में न केवल एम्स के मुख्य लक्ष्यों को शामिल करें, बल्कि इस क्षेत्र की विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान को भी प्राथमिकता दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संगठन के स्वस्थ विकास में सुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरूआत में ही उठाए गए कदमों का इस संस्थान के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशा केवल एक व्यवसाय नहीं है; यह मानवता की सेवा के प्रति एक प्रतिबद्धता भी है। यह पेशा न केवल वैज्ञानिक ज्ञान की मांग करता है बल्कि इसमें संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो सफेद कोट पहनते हैं, वह बीमारी और अनिश्चितता के क्षणों में समाज द्वारा उन पर किए गए भरोसे का प्रतीक है जो मरीज बीमारी और अनिश्चितता के क्षणों में उन पर करता है। इस भरोसे को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी डॉक्टरों के कंधों पर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति अभूतपूर्व गति से हो रही है। आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ चिकित्सा जगत के स्वरूप और संभावनाओं को तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे इन बदलावों को अपनाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीकों को अपनाकर, वे न केवल अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा पाएँगे, बल्कि बीमारियों का अधिक प्रभावी ढंग से इलाज भी कर पाएँगे। हालाँकि, चिकित्सा में मानवीय संवेदना की भूमिका की जगह कोई और नहीं ले सकता। एक डॉक्टर के कोमल शब्द, आश्वस्त करने वाली मुस्कान और मरीज को सुनने का धैर्य, बीमारी को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं, जो सिर्फ दवाएँ नहीं कर सकतीं।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालाँकि, ईमानदारी, करुणा और परोपकार की भावना जैसे मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत डॉक्टर होना इससे भी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कुशल और सामाजिक रूप से जागरूक डॉक्टरों में समाज में गहरा बदलाव लाने की शक्ति होती है। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी स्थिति का रचनात्मक उपयोग करके राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये प्रयास पहले से ही सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। हालांकि, इन पहलों को और अधिक गति तब मिलेगी जब सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में, एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हें चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करके देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को दिशा दिखाने का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एम्स राजकोट, सभी के लिए समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर नए मानक स्थापित करेगा।

सरकार ने स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने हेतु ₹10,000 करोड़ की राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की अधिसूचना जारी की

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0; गहन प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक विकास चरण और नवाचार आधारित विनिर्माण स्टार्टअप का समर्थन करेगा

(जीएनएस)।

सरकार ने कुल ₹10,000 करोड़ की राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0) की अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उद्यम और विकास पूंजी जुटाना है।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0; स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस 1.0) के मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है, जो 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत शुरू किया गया था ताकि वित्तपोषण की कमी को पूरा किया जा सके और स्टार्टअप्स के लिए घरेलू पूंजी को उत्प्रेरित किया जा सके।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 के पास 16वीं और 17वीं वित्त आयोग की अवधि के दौरान पात्र वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की प्रतिबद्धताओं के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि होगी।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 के तहत निवेश उन वैकल्पिक निवेश कोष पर केंद्रित होंगे जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का समर्थन करते हैं, जिनमें गहन प्रौद्योगिकी (डीप टेक) स्टार्टअप्स, छोटे एआईएफ द्वारा समर्थित प्रारंभिक विकास चरण के स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी-संचालित और नवाचार आधारित निर्माण स्टार्टअप्स तथा क्षेत्र या चरण से स्वतंत्र स्टार्टअप शामिल हैं।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 एआईएफ के लिए एक संरचित चयन प्रक्रिया का पालन करेगा, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी लोगों से बने उद्यम पूंजी निवेश समिति (वीसीआईसी) द्वारा स्क्रीनिंग शामिल होगी। इस योजना में मजबूत निगरानी और निरीक्षण तंत्र शामिल हैं तथा योजना के कार्यान्वयन और प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) भी गठित की जाएगी। इसमें एक व्यापक रूपरेखा के तहत उचित शासन सुरक्षा के साथ सरकार और संस्थागत निवेशकों द्वारा सह-निवेश के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) वीसीआई की संरचना और संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगा।

उम्मीद है कि स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, भारत के नवाचार-प्रेरित विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन स्टार्टअप्स का समर्थन करेगा, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियां, उत्पाद, और समाधान तैयार करते हैं। यह योजना भारत की आर्थिक दृढ़ता को मजबूत करने, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन करने और भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान देगी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अधिसूचना की तारीख से योजना के कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में योजना के संचालन की शुरूआत करेगा । इसके अलावा, प्रस्तावित योजना को लागू करने के लिए एक अन्य घरेलू कार्यान्वयन एजेंसी का भी चयन किया जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, केंद्रीय सरकार द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में निवेश करने के लिए सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) की निधि में योगदान देगा।

विकसित भारत @ 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप, यह कोष उद्यमियों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की पूरी संभावनाओं को सामने लाने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्नत कृषि महोत्सव का भव्य समापन, किसानों के साथ कृषि बदलाव का नया संकल्प

शिवराज सिंह चौहान की मांग पर नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, रायसेन रिंग रोड और सौंदर्यीकरण कार्यों को मिली मंजूरी

किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा- नितिन गडकरी

एआई, ड्रोन, नैनो यूरिया और नवाचार से घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन- नितिन गडकरी

जल संरक्षण, डेयरी, मत्स्य और प्रोसेसिंग से बढ़ेगी किसानों की आमदनी- नितिन गडकरी

यह समापन नहीं, नई शुरूआत है; रोडमैप को जमीन पर उतारेंगे- शिवराज सिंह चौहान

बीज से बाजार तक की योजना पर अमल के लिए बनेगी टास्क फोर्स- शिवराज सिंह चौहान

किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे- शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कृषि मेले 'उन्नत कृषि महोत्सवद्ध का रायसेन में अत्यंत उत्साह, उमंग, नवाचार और हजारों किसानों की गरिमामयी उपस्थिति के बीच भव्य समापन हुआ। समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जहां सड़क विकास, कृषि तकनीक, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि का व्यापक विजन रखा, वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज से बाजार तक तैयार रोडमैप को जमीन पर उतारने का दृढ़ संकल्प दोहराया।

शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ

रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित 'उन्नत कृषि महोत्सवद्ध के समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई क्षेत्रीय मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते हुए विकास की नई सौगात दी। उन्होंने रायसेन रिंग रोड/पूर्वी बायपास के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने, संबंधित डीपीआर तैयार करने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जाने और पुलों के सौंदर्यीकरण संबंधी मांगों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सड़क संबंधी प्रस्तावों पर भी जो संभव सहयोग होगा, वह किया जाएगा।

ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है

अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि किसान के रूप में

आए हैं। उन्होंने कहा कि खेती का भविष्य अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर स्टेशन, सैटेलाइट आधारित सूचना, ड्रोन, नैनो यूरिया और आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़ चुका है, इसलिए किसानों को समय के साथ बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान को संपत्ति में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने किसानों से इनोवेशन, रिसर्च, सफल प्रयोगों और तकनीक-आधारित खेती को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन संभव हो सके।

श्री गडकरी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, डामर दाता और हाइड्रोजन दाता भी बनेगा। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेष, पराली, बायोमास, इथेनॉल, सीएनजी और हाइड्रोजन के माध्यम से किसानों के लिए आय के नए रास्ते खुलेंगे, आयात घटेगा और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी।

जल संरक्षण पर विशेष बल

जल संरक्षण पर विशेष बल देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि दौड़ते हुए पानी को चलने के लिए, चलने वाले पानी को रुकने के लिए और रुके हुए पानी को जमीन को पिलाने के लिए लगाना होगा। उन्होंने 'गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर मेंद्ध का संदेश देते हुए कहा कि जैसे पैसा बैंक में जमा किया जाता है, वैसे ही पानी को जमीन में डिपॉजिट करना होगा।

उन्होंने कहा कि जहां सिंचाई का पानी सीधे नहीं पहुँच सकता, वहां जल संरक्षण की संरचनाएँ बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

उन्होंने डेयरी, मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी को किसानों की आय बढ़ाने के बड़े माध्यम बताते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। श्री गडकरी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग सिस्टम और वैल्यू एडिशन की मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि जब बाजार में उत्पादन अधिक होता है तो कीमतें गिर जाती हैं, इसलिए भंडारण और प्रसंस्करण की मजबूत व्यवस्था किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे मेले में लगे स्टॉल, मशीनरी प्रदर्शन, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एक एकड़ खेती के मॉडल, बकरी पालन, मछली पालन और अन्य तकनीकी सत्रों को देखकर जाएँ, सीखकर जाएँ और उसे खेत में लागू करें। उन्होंने कहा कि यही ज्ञान, यही तकनीक और यही प्रयोग किसानों का भविष्य बदलेंगे, गांवों को समृद्ध बनाएंगे और स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की दिशा को मजबूत करेंगे।

शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल की म.प्र. की कृषि उपलब्धियों की सराहना

श्री गडकरी ने शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रीत्व कार्यकाल में मध्य प्रदेश की कृषि उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं और यह महोत्सव किसानों को भविष्य की नई प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा।

यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरूआत है

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'उन्नत कृषि महोत्सवद्ध कोई कर्मकांड नहीं है और यह समापन नहीं, बल्कि नई शुरूआत है। उन्होंने कहा कि चार दिनों तक चले इस आयोजन ने किसानों के लिए पाठशाला का काम किया, जहाँ मिट्टी की महक, मशीन की शक्ति, नवाचार, तकनीक और विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र की माटी, जलवायु, जल उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर बीज से बाजार तक का विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रोडमैप में यह तय किया गया है कि इस क्षेत्र में कौन-कौन सी फसलें, फल और सब्जियाँ अच्छी हो सकती हैं और उनके उत्पादन, प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग की संपूर्ण योजना कैसे बनेगी।

दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अच्छे बीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर ब्लॉक में बीज ग्राम बनाए जाएंगे, दलहन और बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी की एक-एक बूंद का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायतों में मशीन बैंक बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को आधुनिक मशीनें आसानी से मिल सकें। श्री चौहान ने कहा कि अच्छी नर्सरी और क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, एफपीओ को मजबूत किया जाएगा, बैक हाउस और कोल्ड हाउस बनाए जाएंगे और किसानों को उत्पादन से बाजार तक बेहतर ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकीकृत खेती के मॉडल के माध्यम से छोटे खेत के टुकड़े पर भी अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है और सरकार किसानों की आय बढ़ाकर ही चैन की सांस लेगी।

रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे रोडमैप की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी तथा राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि जो संकल्प लिए गए हैं, वे केवल घोषणा बनकर न रह जाएँ, बल्कि पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरें।

डीआरडीओ बिहार के मोतिहारी में आयोजित होने वाली विशाल प्रदर्शनी के दौरान देश की अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत पहल का भव्य प्रदर्शन करेगा

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) 15 से 18 अप्रैल, 2026 तक बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाली भव्य प्रदर्शनी के दौरान अपनी अत्याधुनिक तकनीकों, उन्नत रक्षा प्रणालियों और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में किए जा रहे सशक्त प्रयासों का व्यापक प्रदर्शन करेगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन संसद सदस्य एवं रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया जाएगा। इस प्रदर्शनी की विषयवस्तु 'शांति, सत्य और विज्ञान का संगम - सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर' रखी गई है।

प्रदर्शनी में उन्नत रक्षा प्रणालियों से युक्त अत्याधुनिक मॉडलों और स्वदेशी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यूएंडसी) सिस्टम, आकाश सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल, आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) मिसाइल लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल, नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, प्रलय मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम), एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस), पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (एमएलआरएस), मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन एमके-क्क&क्क, भारतीय लाइट टैंक (आईएलटी), मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन रडार, उत्तम एईएसए रडार, होलोग्राफिक साइट, ऑटोमैटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म (एसीएडीए) सिस्टम, केमिकल एजेंट मॉनिटर (सीएएम), केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर (सीबीआरएन) जल शुद्धिकरण प्रणाली (सीबीआरएन-डब्ल्यूपीएस), बैक पैक-5केजी, ए नबीसी सूट एमके-श, मल्टी-फंक्शनल माउंटेड गन सिस्टम (एमजीएस), व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूएचएपी) के लिए कंपोजिट आर्मर, कावेरी इंजन का रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल, कावेरी इंजन का स्पेशल रियलिटी डिस्प्ले, ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट, बैलिस्टिक हेलमेट, नौसेना स्टील और अन्य सामग्री प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें डीआरडीओ द्वारा विकसित उन अत्याधुनिक तकनीकों एवं प्रणालियों को करीब से देखने व समझने का अवसर प्रदान करेगा, जो देश की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बना रही हैं।

अंबेडकर जयंती पर लखनऊ पहुंचने का बसपा का आह्वान:बसपा नेता अकील अंसारी बोले–लखनऊ में जुटें कार्यकर्ता

मो. इमरान अंसारी

बिजनौर के चांदपुर निवासी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के जिला उपाध्यक्ष अकील अंसारी ने कार्यकताओं और जनता से 14 अप्रैल 2026 को लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया है। यह आह्वान भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के लिए किया गया है।

अकील अंसारी ने बताया कि यह कार्यक्रम बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के आह्वान पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकताओं से अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहने वाले लोगों को बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर यह संदेश देना होगा कि वे 2027 में मायावती को पांचवीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। अकील अंसारी ने बसपा सरकार के दौरान हुए विकास और आपसी भाईचारे का जिक्र किया।

उन्होंने दावा किया कि ऐसा विकास और सौहार्द आज तक देखने को नहीं मिला। उन्होंने सर्व समाज से अपील की कि यदि वे प्रदेश को तरक्की के पथ पर ले जाना चाहते हैं, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार, बीमारों को चिकित्सा सुविधा और बहनों को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो बसपा ही एकमात्र विकल्प है।

उन्होंने एक बार फिर जिले की जनता से 14 अप्रैल 2026 को गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की।

स्वच्छता पखवाड़ा, 2026 के अंतर्गत विधायी विभाग ने 'जल निकायों का सुधार' कार्यशाला का आयोजन किया

(जीएनएस)।

स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने डॉ. राजीव मणि, सचिव, विधायी विभाग के मार्गदर्शन में 13 अप्रैल 2026 को शास्त्री भवन की चौथी मंजिल स्थित सम्मेलन कक्ष क्रमांक 440-ए में "जल निकायों का सुधार" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य जल निकायों के संरक्षण और सुधार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जल सुरक्षा बढ़ाने और लगातार विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना था।

कार्यशाला में संयुक्त सचिव श्री गैनीलुंग पानमेई और अतिरिक्त विधायी वकील श्री आर.एस. जयकृष्णन के साथ-साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें राजभाषा विभाग (ओ.एल. विंग) और विधि साहित्य प्रकाशन (वीएसपी) के सहयोगी कार्यालय भी शामिल थे।

इंडिया-एड्स (एनजीओ) की ओर से श्री मधुकर स्वयंभू ने एक विशेषज्ञ सत्र प्रस्तुत करते हुए पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए जल निकायों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस विषय पर बल दिया कि सुव्यवस्थित जल निकाय पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता को प्रोत्साहन देने, वायु प्रदूषण को कम करने और भूजल को दोबारा भरने में सहायक होते हैं। विशेषज्ञ ने यह भी जानकारी दी कि स्वच्छ जल निकाय हैजा और टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियों को रोकते हैं, जबकि उचित रखरखाव मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है।

संयुक्त सचिव श्री गैनीलुंग पानमेई ने विशेषज्ञ के योगदान की सराहना की और जल निकायों के जीर्णोद्धार और संरक्षण की दिशा में लोगों, समाज और सरकारी नीतियों/परियोजनाओं की ओर से निरंतर जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

लखनऊः पीएम मोदी को लेकर लिखी अभद्र पोस्ट, सीएम योगी की फोटो एडिट करके किया शेयर; दर्ज हुआ केस

लखनऊ , (जीएनएस)।

दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। चिनहट, इंदिरानगर के इन दोनों मामलों में केस दर्ज किया गया है।

चिनहट निवासी सतेंद्र कुमार ने इंस्टाग्राम आईडी वन क्रिएटर के संचालक नितिन विश्वकर्मा पर पर प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अभद्र वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। बीबीडी पुलिस ने सतेंद्र की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

सतेंद्र का आरोप है कि नितिन इंस्टाग्राम के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये देश की बहन-बेटियों और पीएम को लेकर गाली-गलौज करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहा है। वह बीबीडी यूनिवर्सिटी की छात्राओं के बारे में भी खुलेआम अभद्र शब्द कहता है। सतेंद्र का कहना है कि नितिन की भाषा शैली से प्रतीत होता है कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही वह गैरकानूनी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। आरोपी के वीडियो के चलते बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी का पता लगाया जा रहा है।

सीएम की फोटो एडिट कर फेसबुक पर की पोस्ट

इंदिरानगर के सुगामऊ निवासी दिलीप लोधी ने विजय श्याम यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट कर उसे आपत्तिजनक बना कर फेसबुक पर पोस्ट करने का आरोप लगाया है। हजरतगंज पुलिस ने शनिवार को आरोपी विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

दिलीप के मुताबिक कुछ दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर मुख्यमंत्री की एडिट की हुई फोटो देखी। फोटो विजय श्याम ने पोस्ट की थी। इतना ही नहीं आरोपी ने अभद्र बातें भी लिखी थीं। दिलीप का आरोप है कि आरोपी ने यह हरकत विभिन्न वर्गों व जातियों में रोष पैदा करने के लिए की है। इससे सामाजिक व धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। इंस्पेक्टर ने विक्रम सिंह के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्य संकलन होने पर कार्रवाई की जाएगी।

उद्घाटन से पहले ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें तय, कार का एक तरफ का देना होगा 275 रुपये

(जीएनएस)।

लखनऊ। सूबे की राजधानी से कानपुर का सफर कम समय वाला होने के साथ ही खचीर्ला भी होगा। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ से कानपुर सिर्फ 35 मिनट में पहुंचने के लिए कार का टोल 275 रुपये चुकाना होगा और चौबीस घंटे में वापसी करने पर टोल 415 रुपये होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अभी नई टोल की दरें जारी नहीं की हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे शुरू होते ही नई टोल की दरें सभी टोल पर चस्पा कर दी जाएंगी। प्राधिकरण ने नई टोल की दरों को लेकर टेंडर प्रकिया को फाइनल कर दिया गया है।

एनएचएआई ने लखनऊ से कानपुर के बीच 63 किमी. का एक्सप्रेसवे 4700 करोड़ की लागत से बनाया है। प्राधिकरण का दावा है कि छह लेन के एक्सप्रेसवे का सफर सुविधाजनक के साथ-साथ आरामदायक भी होगा। यह सुविधाओं से जहां लैस होगा, वहीं हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सौ से अधिक अलग-अलग प्रकार के कैमरे लगाए गए हैं।

एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ से कानपुर के बीच पड़ने वाले टोलों में शिवपुरा (खांडेदेव), बनी, अमरसास और आजाद चौक टोल है। इनमें कही बीच से चढ़ने व उतरने पर टोल की दरें भी कम होंगी। वहीं लखनऊ से कानपुर के बीच पहले से बने राष्ट्रीय राजमार्ग

(एनएच 27) पर टोल मात्र 95 रुपये ही देना होगा और चौबीस घंटे में लौटने पर 145 रुपये।

वार्षिक फास्टैग से पंद्रह रुपये में सफर

एनएचएआई के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा कहते हैं कि अगर लखनऊ से कानपुर के बीच किसी का अकसर आना जाना होता है तो वह वार्षिक पास का उपयोग कर सकते हैं। यह पास 3075 रुपये का है। इस सुविधा से दो सौ ट्रिप यात्रा एक वर्ष में कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे व राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिर्फ पंद्रह रुपये के आसपास खर्च एक टोल पर आता है। एनएचएआई का दावा है कि देश भर के 1150 से अधिक प्राधिकरण के टोल पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

एक्सप्रेसवे का टोल महंगा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनवाता है। एक्सप्रेसवे छह से आठ लेन वाले होते हैं, ये सभी सिग्नल-फ्री होते हैं। इनके निर्माण में तकनीक, सामग्री और सुरक्षा पर अधिक खर्च होता है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार (100-120 किमी/घंटा) से गाड़ियां चलती हैं, जिससे कम समय और कम ईंधन में यात्रा पूरी होती है। एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट पाइंट्स सीमित होते हैं, जिससे जाम की समस्या नहीं होती और सफर आरामदायक होता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग चार लेन के होते हैं। यहां कुछ जगह कट दे दिए जाते हैं। गति सीमा हल्के वाहनों के लिए 100 किमी. प्रति और भारी वाहनों के लिए अस्सी किमी. प्रति घंटे होती है। एक्सप्रेसवे की तुलना में सड़कों की गुणवत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग पर उन्नीस होती है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस (एनई छह) पर टोल की दरें

वाहनों की श्रेणी - एकल यात्रा 24 घंटे में वापसी यात्रा 50 सिंगल यात्रा एक माह में

कार, जीप, वैन - - 275 रुपये - 415 रुपये - - 9220 रुपये

हल्के वाणिज्यक वाहन 445 रुपये - 670 रुपये - 14,890 रुपये

बस व ट्रक - 935 रुपये - 1405 रुपये - 31,200 रुपये

एक्सेल वाणिज्यक वाहन 1020 रुपये - 1530 रुपये - 34,040 रुपये

नोट : यह सूची एनएचआइ द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की समीक्षा बैठक

मध्यप्रदेश में ब्लैक स्पॉट्स के समयबद्ध सुधार एवं सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने पर विशेष जोर

(जीएनएस)।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को जिला रायसेन, मध्यप्रदेश में दौरा हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (टङ्गफ्छल्ल) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (ठलअक), भोपाल क्षेत्र के अधिकारियों के साथ प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश में चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट्स की समुचित पहचान कर उनका निर्धारित समय-सीमा में स्थायी सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लैक स्पॉट पर आवश्यकतानुसार ज्योमेट्रिकल सुधार, उपयुक्त साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, लाइटिंग तथा अन्य इंजीनियरिंग उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और यातायात अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

मंत्री श्री गडकरी ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भूमि अधिग्रहण की स्थिति तथा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सड़क अवसंरचना का विकास केवल कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है।

इस दौरान यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे यात्रा समय में कमी, ईंधन की बचत तथा सड़क सुरक्षा में सुधार परिलक्षित हो रहा है। साथ ही, बेहतर सड़क नेटवर्क के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों एवं औद्योगिक वस्तुओं के आवागमन में तेजी आई है, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है तथा सप्लाई चेन अधिक प्रभावी हुई है।

मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बेहतर कनेक्टिविटी के कारण प्रदेश के पर्यटन स्थलों तक पहुंच अधिक सुगम हुई है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी गति मिल रही है।

टङ्गफ्छल्ल एवं ठलअक के अधिकारियों द्वारा मंत्री श्री गडकरी को अवगत कराया गया कि प्रदेश की अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं तीव्र गति से प्रगति पर हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण खंडों के पूर्ण होने के साथ ही आमजन को बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। विशेष रूप से बायपास, सर्विस रोड, मार्ग पुनर्संरेखन तथा आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग से सड़कों का इस प्रकार विकास किया जा रहा है कि यातायात का दबाव कम हो और यात्रा अधिक सुविधाजनक बन सके।

सावधान ! दोस्ती के बहाने अश्लील वीडियो और फर्जी आईडी: लखनऊ की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के साथ खौफनाक साज़िश

घिनौने करतूत के बाद, 10 लाख की डिमांड की. पैसे नहीं मिलने पर वीडियो-फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को होटल ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दरिंदगी.

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को प्रेमजाल में फंसाकर एक व्यवसायी ने खुद को अकेला बताकर युवती से दोस्ती की. फिर मुंशी पुलिया स्थित एक होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की. आरोपी ने न केवल इस घिनौनी करतूत का वीडियो बनाया, बल्कि उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी.

रकम न मिलने पर आरोपी ने पीड़िता के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर दिए और उसका मोबाइल नंबर भी वायरल कर दिया. इंदिरानगर पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत के कड़े आदेश पर आरोपी सोनू सिंह और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू किया जाल बिछानाः पीड़िता के अनुसार, आरोपी सोनू सिंह उर्फ सोनू वर्मा ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. सोनू ने खुद को अपनी पत्नी से 4 साल से अलग बताया और पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. आरोप है कि मई 2025 में आरोपी उसे मुंशी पुलिया स्थित होटल ले गया, वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेसुध किया और रेप कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया.

10 लाख रंगदारी की मांगः वीडियो बनाने के बाद आरोपी असली रंग में आ गया, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये मांगे. जब पीड़िता रकम नहीं दे पाई, तो आरोपी ने उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उस पर अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड कर दिए. आरोपी ने वीडियो के साथ पीड़िता का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया, जिससे उसे अनजान नंबरों से गंदी कॉल आने लगीं और उसकी सामाजिक बदनामी हुई.

कोर्ट के आदेश पर एक्शनः पीड़िता ने पहले इंदिरानगर पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी सोनू सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज किया है. प्रियंका पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. एसीपी गाजीपुर अनिंद्य विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जल्द ही पीड़िता के बयान दर्ज कराए जाएंगे. साक्ष्य और डिजिटल एविडेंस के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

मेरठ सेंट्रल मार्केटः लखनऊ से आज पहुंचेगी टीम, अवैध निर्माण पर जल्द जारी होंगे नोटिस, व्यापारियों में चिंता

मेरठ , (जीएनएस)। मेरठ के सेंट्रल मार्केट सीलिंग मामले में आज लखनऊ से आवास एवं विकास परिषद की टीम पहुंचेगी। अवैध निर्माण को लेकर 10-15 दिन के नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।

मेरठ के सेंट्रल मार्केट सीलिंग मामले में सोमवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नियोजन विभाग की टीम आज लखनऊ से मेरठ पहुंचेगी। टीम के आगमन से छोटे भवनों और दुकानों को लेकर बने असमंजस के हालात साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि छोटे भूखंडों पर बने मकानों और दुकानों में कितना सेटबैक (खुला स्थान) छोड़ना अनिवार्य होगा। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। दूसरी ओर आवास एवं विकास परिषद द्वारा आज से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की संभावना है।

छोटे भूखंडों में सबसे बड़ी समस्या

नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तहत व्यावसायिक और आवासीय दोनों प्रकार के भवनों में सेटबैक छोड़ना अनिवार्य है। सेंट्रल मार्केट के सेक्टर-2 में स्थिति अधिक जटिल है, क्योंकि यहां कई मकान सिर्फ 25 मीटर और 38 मीटर के छोटे भूखंडों पर बने हुए हैं।

इनमें भूतल पर दुकानें संचालित होती हैं, जबकि ऊपर लोग रहते हैं। यदि नियमों के अनुसार सेटबैक छोड़ा गया तो अधिकांश दुकानों और मकानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

पुराने भवनों को लेकर भी चिंता

व्यापारियों की चिंता सिर्फ जगह कम होने तक सीमित नहीं है। सेंट्रल मार्केट के कई निर्माण करीब 35 से 40 साल पुराने हैं। छोटे दुकानदारों ने इन इमारतों को दोबारा बनाने के बजाय समय-समय पर केवल मरम्मत कराई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सेटबैक के लिए इन पुराने ढांचों में तोड़फोड़ की गई तो पूरी इमारत गिरने का खतरा भी बन सकता है।

आज होगा तकनीकी मंथन

आवास एवं विकास परिषद के चीफ आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर संजीव कश्यप अपनी टीम के साथ सोमवार को इस पूरे मामले पर मंथन करेंगे। टीम स्कीम नंबर-7 के जोनल प्लान और मौजूदा निर्माण की स्थिति का मिलान कर नियमों के अनुरूप

पोर्टर और गिगिन टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से रोजगार माध्यम बढ़ाने के लिए पोर्टर और गिगिन टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

डॉ. मनसुख मांडविया ने एनसीएस को युवाओं को कौशल-आधारित अवसरों से जोड़ने वाले एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला मंच बताया

पोर्टर बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स और ड्राइविंग के अवसर पैदा करेगा; इसका लक्ष्य 2030 तक 30 लाख से अधिक अवसर सृजित करना है

गिगिन एनसीएस के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक नियोक्ताओं के साथ जुड़कर प्रति वर्ष 2-3 लाख सत्यापित रोजगार के अवसर सृजित करने में सक्षम होगा

(जीएनएस)।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख

मांडविया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री वंदना गुरनानी की उपस्थिति में पोर्टर और गिगिन टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और डिजिटल नौकरी मिलान को मजबूत करना है।

इस अवसर पर, श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, ह्लएनसीएस प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए उनकी कौशल क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर तलाशने का एक प्रभावी और संपूर्ण समाधान बनकर उभरा है। पोर्टल पर वर्तमान में 7 लाख से अधिक रिक्तियां सक्रिय हैं और लगभग 59 लाख प्रतिष्ठान एनसीएस पर पंजीकृत हैं, इससे युवा नौकरी चाहने वालों के लिए अनेक अवसर खुल गए हैं ह्ल केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीएस की गिगिन और पोर्टर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी सभी हितधारकों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी और एनसीएस पोर्टल को और सशक्त बनाएगी।

डॉ. मांडविया ने एनसीएस पोर्टल के ई-माइग्रेट, एसआईडीएच और माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के पोर्टलों के साथ एकीकरण पर प्रकाश डाला। इससे यह वास्तव में व्यापक और परिवर्तनकारी पहुंच वाला पोर्टल बन गया है। कौशल अंतर की समस्या को दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने एनसीएस के साथ-साथ गिगिन और पोर्टर से पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया, ह्लनौकरी चाहने वालों की मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कौशल अंतर को पाटने और हमारे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक होंगे ह्ल

श्रम एवं रोजगार सचिव, सुश्री वंदना गुरनानी ने एनसीएस पोर्टल के व्यापक पैमाने और प्रभाव के बारे में कहा कि इसकी स्थापना के बाद से ही इसने 6 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों को पंजीकृत करने के साथ ही 9 करोड़ से अधिक रिक्तियों को सृजित किया है।